यू एल एफ ए द्वारा बातचीत के प्रस्ताव के पश्चात् उसकी हिंसक गतिविधियों में वृद्धि

†1123. **श्री वीरेन जे शाह :**
श्री प्रमोद महाजन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित दिनांक 11 फरवरी, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एर्ट इन वायलेंस आफ्टर टाक्स आफर" शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि विशेषतया यू.क.ल.एफ. द्वारा सरकार के साथ बातचीत करने के अप्रत्याशित प्रस्ताव के पश्चात् हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार हिंसा की घटनाओं में हो रही वृद्धि से निपटने हेतु क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) समाचार देखा है ।

(ख) उल्फा से संबंधित हिंसा से निपटने की कार्रवाई योजना की समीक्षा की गई । संवेदनशील क्षेत्रों में सेना गश्त लगा रही है । जांच गहन कर दी गई है। स्थिति का गंभीरता से प्रबोधन किया जा रहा है ।

SHRI VIREN J. SHAH: Sir, I have very high respect for this hon. Minister but I regret to say that his reply is hardly meaningful. If you to back to this very hon. Minister's statements on ULFA and Assam when I had tabled up a Private Member's Resolution last year, he has been giving the same kind of replies "It is under consideration.

समीक्षा की जा रही है वगैरहा

†सभा में यह प्रश्न श्री वीरेन जे. शाह द्वारा पूछा गया ।

Even in this news paper's report it says and I want to quote one sentence "Indeed, there has been a spurt in violence of late, especially after the unexpected offer from the ULFA for talks with the Central Government." Then, it goes on to say about specific attacks on political parties: the Chairman of the Congress (I) Mr. Hiteshwar Saikia's nephew was killed, the General Secretary of the Congress (I) party was killed and several others were killed. With that situation this reply does not lead us anywhere. Will the hon. Minister kindly specify whether there is reduction in the criminal acts of ULFA? An organisation like that declares cease-fire as if two Armies from two nations are fighting. The hon. Minister is also reported to have said that he has welcomed the cease-fire. In this context in reality what is happening there and how are we proceeding to curb the violence of ULFA?

श्री सुबोध कान्त सहाय : सभापति महोदय, मैं अभी चार दिनों के दौरे से उस इलाके से आ रहा हूं । एक एक जिले के डिप्टी कमिश्नर और एस. पी. के साथ वार्ता करके कानून और व्यवस्था की सारी प्रक्रिया की समीक्षा करके आ रहा हूं । "उल्फा" ने 28 तारीख को यूनिलेटरल सीज फायर की घोषणा की है । उसके पहले प्रधानमंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि वे किसी भी इस तरह की शक्तियों से बात करने के लिये संविधान के तहत तैयार हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले सरकार अपनी अथारिटी असर्ट कर रही है । उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसमें हिंसा और किलिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है । हकीकत यह है कि उन्होंने एक खास पार्टी को अपना टारगेट भी बनाया है । उनकी सुरक्षा के लिये, जितने भी ऐसे लोग हैं, करीबन दो सौ लोगों की सुरक्षा के लिये हमने व्यवस्था की है जिन्हें पर्सनल सेक्युरिटी दी जा सकती है । रहा सवाल, घटनाओं में कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन जब सरकार एफर्ट्स

करती है तो उसका रीऐक्शन होता है । आज वहां पर हर एक जिले के प्रशासन को ब्रूटली पुश-अप करना पड़ रहा है । जिससे वे एफेक्टिव हों । उनकी सारी मशीनरी चाहे वह थाने में जहां पर वेहिकिल्स नहीं हैं, वायरलैस नहीं हैं, आर्म्स नहीं हैं, असम के एक एक डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह से रिवाइव करके टोन-अप किया जा रहा है जिससे एफेक्टिवली वहां पर इक्विनिस्ट्रेशन का काम चले । सभापति महोदय, यही नहीं यह भी संभावना है कि "उल्फा" के लोग बड़े पैमाने पर आत्म-समर्पण करें । लेकिन हमारा प्रेशर और प्रयास बना रहेगा वार्ता का । उनके कई मिनिस्टर आये हैं, अभी हम लोगों के साथ उनका डाइरेक्ट सम्पर्क नहीं हुआ है, लेकिन हम यह समझते हैं कि अगर उन्होंने यूनिलेटरल सीज फायर की घोषणा की है तो यह एक शुभ लक्षण है । लेकिन उसके बाद एक घटना हुई है । वहां पर एक डाक्टर की हत्या हुई है । उस डाक्टर की हत्या "उल्फा" के द्वारा हुई है या किसी और के द्वारा हुई है, लेकिन यह घटना हुई है और इसके बारे में पूरी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं आई है । लेकिन मैं समझता हूं वास्तव में स्थिति में सुधार हुआ है, लोग लौट रहे हैं सेंस आफ कानफिडेंस बिल्ड-अप हुआ है, टी गार्डन्स के इलाके में लोग काम कर रहे हैं और एक पोजिटिव एचीवमेंट हमारे सामने है ।

SHRI VIREN J. SHAH: Last year, several Members, and I, particularly, had mentioned that in Assam, the Government should take very strong action. The previous Government could not do it for whatever reasons it had. But this Government has taken the action of having President's rule there and I would compliment this Government on that count. Yet, here is the report on 4th March of the newspaper "Business and Political Observer". It says that the ULFA has given a threat asking members of all national parties to quit their respective parties by March 30th or face dire consequences. This has been strongly objected to by several parties. Is it true that such a threat has been given? If so, what are the action being taken by the Government of India which is the Government in Assam?

श्री सुबोध कान्त सहाय : सभापति महोदय, यह बात सही है कि राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं के ऊपर उल्फा के नेताओं ने थ्रैट दिया है, चेतावनी दी है लेकिन इसकी वहां की तमाम पार्टियों के लोगों ने बढ़ कर के भर्त्सना की है तथा इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो करके प्रयास करने का फैसला भी लिया है । उन लोगों ने यह भी कहा है कि इसके लिए काउंटर मूवमेंट चलाएं जिससे जनसम्पर्क और जन-अभियान शुरू किया जाए । उस स्तर पर अगर कोई पार्टी वहां करना चाहती है कि इस हिंसा की भर्त्सना करते हुए लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया जाए और सरकार के साथ अगर मिल कर के जो उसमें कमी और बेशी हो उसके साथ काम करने की कोशिश करेंगे तो सरकार उनका पूरी तरह से साथ देगी ।

श्री वीरेन जे० शाह : क्या वैसा वातावरण बन रहा है ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : दो तीन पार्टियों के नेताओं ने यह कहा है कि वे लोग अपना कार्यक्रम बना रहे हैं और इसकी सम्भावना है ।

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Is it a fact that the former Chief Minister and the former Home Minister are actively connected with ULFA activities and if so, what action has the Government taken against them also?

श्री सुबोध कान्त सहाय: सभापति जी, जिन राजनीतिक दलों के लोगों के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है मैं यह मानता हूं कि कहीं न कहीं वे निकम्मा जरूर रहे हैं जिसके चलते आज पूरे आसाम राज्य की ऐसी स्थिति हुई है । पूरी तरह से उनका कोई संबंध रहा है, इसका प्रमाण हमारे पास नहीं है ।

SHRI DINESH GOSWAMI: Mr. Chairman, situation in Assam, after the imposition of President's rule, has not only not improved, but it has become more complicate. Alienation has grown because of the large number of cases of rapes, extra-judicial killings and harassment. This is not what I have said. A four-member team of the PUDR which visited the State has submitted a report which has been extensively reported in the press and which I would not like to go into. On the otherhand, there has also been an increase in the case of individual hit-and-run killings. I think, after the imposition of President's rule, more persons have been killed than in the year before. Now, it will require a political solution. And one of the political solutions is to sit across the negotiating table. I was happy that the Prime Minister assured this House that he is prepared to talk with any militant organisation, including the ULFA provided the initiative comes from them. I have come to know—and it has been reported in the press—that the ULFA have themselves offered for talks through a letter to the Governor of Assam and they have now there what has been described as ceasefire. That means the operation has stopped. I would like to know from the Prime Minister whether he is now prepared to responed to this offer and initiate a dialogue at any level that they may think appropriate and in any manner he may choose.

SHRI CHANDRA SHEKHAR: Mr. Chairman, Sir, I do not agree with the hon. Member that the situation has deteriorated there after the imposition of Presirent's rule. There has been some killings in the recent past and that is very unfortunate. And he knows what elements are responsible for those killings. I assure the hon. Member, as I said earlier in another context, that we are ready to negotiate or talk with anybody. But two conditions are pre-requisites of such talks. Talks should be within the framework of the Indian Constitution and nobody should question the authority, integrity and the sovereignty of this nation. That is one thing. And the other thing is that it should not be done on the point of gun. I have read in the papers that they have done ceasefire. There was no war there. So there is no question of ceasefire. They should stop violence. That is one condition. If the hon. Member can use his good offices and they are ready....

SHRI DINESH GOSWAMI: If the Prime Minister cannot, I can't.

SHRI CHANDRA SHEKHAR: I tell you and I honestly say, if they are ready to come and put their grievances before the Government, the Government is ready to accommodate their point of view and do everything possible to see that their grievances are redressed and they function in a democratic manner in a democracy which is the authority. (*Interruptions*).

SHRI VIREN J. SHAH: The ULFA in their recent statement said that Assam is not part of India. How would you deal with that?

SHRI CHANDRA SHEKHAR: That is why I said that they should change that stand. They should say that they consider Assam as part of India and there is no question of *Hamraj*. That cannot be accepted and there cannot be negotiation on that point.

SHRI DINESH GOSWAMI: In view of their letter to the Governor, have you issued any instructions to the Governor and are you in a position to share it if they so desire?

SHRI CHANDRA SHEKHAR: For that no instruction is needed. The Governor or the officials know there that we are not determined to take coercive measures unless and until it becomes imperative. If by negotiated talks there can be some settlement, the Government will welcome it and the Governor knows that this is the policy of the Government.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Mr. Chairman, Sir, I would like from the side of the Government to know whether at the time of the imposition of President's Rule, however regrettable it may be, the Government

thought it was necessary to enforce the Disturbed Areas Act in the whole of Assam. In view of the claim that is being made by the Government, the Disturbed Areas Act should be withdrawn either from the whole of Assam or at least from major portion of Assam which is not affected by terrorist activities. There is no gain saying the fact that terrorism has to be dealt with properly and firmly but at the same time, not with vindictiveness but with an idea to come to a solution of the problem giving rise to terrorism or things like that. In view thereof, this question of Disturbed Areas Act and its withdrawal from Assam should be considered.

SHRI CHANDRA SHEKHAR: Mr. Chairman, Sir, at the moment, there is no proposal before the Government of India to withdraw the Disturbed Areas Act because the situation does not warrant it. But we have taken into consideration all the complaints that have come. My hon. friend says that there were cases of rape and all that. Every individual case was gone into whether it is from the Army or from the armed forces and appropriate measures have been taken to assure the people that nothing will be done which is against the law in the land.

MR. CHAIRMAN: Shri Bhubaneshwar Kalita. (*Interruptions*).

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, I may also be given a chance.

MR. CHAIRMAN: I have given a chance here and then to Mr. Kalita. He also comes from Assam, if I am not mistaken. You can correct me always. (*Interruptions*).

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, the Prime Minister saird that the Government is prepared to talk to ULFA. But since ULFA is a banned organisation, may I know whether the Government is considering to lift that ban. This is what I want to know from the Home Minister.

SHRI CHANDRA SHEKHAR: There is no question of lifting the ban and if the hon. Member heard me attentively, I said, we are ready to talk with any individual or any person. I never mentioned the name of ULFA.

*124. [*The questions (Shri Parumpan Tha Kirutinam and Shri V. Gopalsamy) wert absent. For answer, vide col 34-35 in page*]

Committee to study the technical and cultural impact of foreign satellite programmes on India

*125. SHRI G. SWAMI NAIK:
SHRI KAPIL VERMA:†

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Committee was set up by the Ministry of Information and Broadcasting about two years ago to study the technical and cultural impacts of foreign Satellite programmes on India; if so by when the study report of the committee is likely to be submitted;

(b) whether it is also a fact that prior permission is required to be obtained from the Office of the Advisor (Wireless) for showing programmes on television through Satellite;

(c) whether it is also a fact that the hotels are free to avail of the benefits of Cable News Network (CNN) Services;

(d) whether it is a fact that Doordarshan is likely to be affected by the video magazines to be telecast through cable network; and

(e) if so, what steps are proposed to be taken by Government in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (e) A statement is laid on the table of the House.

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Kapil Verma.